आप लेट हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो बेअंत सिंह, चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था कि मैं अपने खर्चे से शुरू करूंगा बशर्ते की आपका कोलोबोरेशन हो। उन्होने कोलोबोरेशन लिया और लेकर वहां पर इंस्टीट्यूट नवम्बर, 1995 में शुरू किया। जो क्वेश्चन हैं चेयरमैन सर यह निफ्ट का हैं। यह कहा जाता हैं कि नार्दल-इंडिया का जो पंजाब में लगाया गया हैं जिस तरह से कहा जा रहा हैं वह बात गलत हैं। ऐसी कोई बात नहीं हैं।

दूसरी बात यह हैं कि मेम्बर ने कहा कि इसके ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं, इरेम्युलरिटीज हैं। कमेटी डालने की जरूरत हैं। अभी अभी नवम्बर में शुरू हुआ हैं और उसमें जो कोलोबोरेशन निफ्ट के साथ हैं जो यहां दिल्ली में हैं वह उसको टेक्रालाजी का पूरा कोआपरेशन दे रहे हैं। उनकी जो जो जरूरियात हैं उसमें भी उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि वह इंस्टीट्यूट ऊपर आए।

DR. D. MASTHAN: Is there any institute in any other State, which has been set up in collaboration with NIFT?

SHRI G. VENKAT SWAMY: No.

DR. D. MASTHAN: Then, will the Minister take necessary steps to set up such institutions in other States?

SHRI G. VENKAT SWAMY: We will consider about it in future.

MR; CHAIRMAN: Mr. Surinder Singh Singla.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, I am Surinder Kumar Singla.

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Chairman, Sir, I am extremely grateful to the hon. Minister for agreeing to help the State of Punjab in this direction. In fact, being a Member of the Textile Commission, I am myself persuading him to do this, but. the problem is still pending. It is true that today Punjab produces around 25 per cent of cotton in the country. There is a potential for export of garments from Punjab. What is really needed and for which I have been persuading him is to open up a textile garments park. It is actually connected with this. The Centre need not spend a single paisa for putting up this project.' May I know from the Hon. Minister whether he would consider the proposal for setting up of a garment industrial park in Punjab so that we could adequately and properly contribute our share in terms of increasing export of garments to other countries in the world?

श्री जी. वेंकट स्वामी : सर, अगर पंजाब गवर्नमेंट ऐसी कोई प्रोपोजल देती हैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ टैक्सटाइल चाहती हैं कि हर सिटी के अंदर टैक्सटाइल सिटी हो, हर कैपिटल के अंदर टैक्सटाइल पार्क हो और मैं माननीय सदस्य को एशोरेंस देता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऐसी प्रोपोजल आए तो उसको हम एक्सैप्ट करेंगें और जितनी मदद चाहिए उतनी करेंगें।

Location of TV Transmitter at Basot

*162. SHRI JALALUDIN ANSARI;†
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the location of the land identified for setting up a TV transmitter at Basot in District Almora, U.P.;

(b) whether the land has been handed over to Doordarshan;

(c) if so, by when the work on the project is likely to start; and

(d) if not, the reasons therefor and who is responsible for the delay which is affecting the commissioning of the TV transmitter scheduled to start functioning by July, 1996?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAY-EED): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Suitable site/buildings for setting up of TV projects are required to be provided, to Doordarshan by the respective State Governments. No readymade building at Basot was made available by the State

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jalaludin Ansari.

Government for setting up of the VLPT resulting in some delay in implementation of the project. A suitable site for setting up of the Very Low Power TV transmitter (VLPT) at Basot has since been identified and financial sanction for purchasing the same issued. Construction work would commence as soon as possession of the identified site is handed over to Doordarshan. Transmitter equipment for the project has already been procured. The VLPT is expected to be completed during 1996.

श्री जलालुद्दीन अंसारी : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा हैं कि बासोट (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किए जाने वाले टी.वी. ट्रांसमीटर हेतु सरकार द्वारा स्थल की शिनाख्त कर ली गई हैं, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह शिनाख्त कब की गई? टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के लिए अनुमानित राशि क्या हैं एवं सरकार द्वारा स्थल पर कब तक कब्जा मिलने की संभावना हैं?

†**شری جلال الدین انصاری:** سبھا پتی مہودے۔ جیسا کہ منتری مہودے نے میرے پرشن کے اتر میں کہا ہے کہ پاسپورٹ اتر پردیش میں استھاپت کئے جانے والے ٹی۔ وی۔ ٹرانسمیٹر ھیتو سرکار دوارا استھل کی شناخت کری گئی ہے۔ تو میں منتری جی سے جاننا چاہونگا کہ یہ شناخت کب کی گئی ۔ ٹی۔وی۔ ٹرانسمیٹر استھاپت کئے جانے کیلئے انومانت راشی کیا ایونم سرکار دوارا استھل پرکب تک قبضہ ملنے کی سمبھاؤنا ہے۔

SHRI P.M. SAYEED: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member wanted to know about commissioning of a Very Low Power TV transmitter (VLPT) at basot in the district of Almora, U.P. Initially our policy is that for such T.V. projects, land should be made available by the State Governments free of cost. That is the policy of the Government. But, Sir, in this case they have identified two "nali" land which was not suitable for the project to be set up. This was made known to the district authorities and they tried to locate some building. Normally we take a VLPT/LPT on rent. The land was not made available and the building also was not made available to us. They have ear-marked hardly one-third acre of land which means two "nalis". But that is less than the land required for LPT-. I would like to share with the House information with regard to allotment of land for various transmitters with the House. For the purpose of a high-powered transmit- i ter seven acres of land is to be made[1] available and for a very low-powered j transmitter 105 square matres inbuilt area- carpet area and 1,500 square metres of open area is necessary. This land; falls short of that. But as a special case in j spite of land not being made availablej and a building not being made available! we have accepted their proposal and we have issued a sanction letter. As soon asj land is made available, possession of a; building is made available we sould try to; sec that it is done.

श्री जलालुद्दीन अंसारी : महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने कहा हैं कि वर्ष 1996 के अंत तक ट्रांसमीटर चालू किए जाने की संभावना हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे संभव होगा जब कि सरकार को अभी स्थल ही नहीं सौंपा गया हैं तो उपकरण लगाने का काम किस रूप में शुरू किया जा सकता हैं और यह कार्य वर्ष 1996 में कैसे संपन्न हो सकेगा?

†**شری جلال الدین انصاری:** مہودے۔ جیسا کہ منتری جی نے کہا ہے کہ ورش ۱۹۹۶ کے انت تک یہ ٹرنسمیشن چالو کئے جانے کی سنمبھاونا ہے۔ میں مانئے منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے سنمبھئو ہوگا جب کہ سرکار کو ابھی

†Transliteration in Arabic Script

استھل ہی نہیں سونپا گیا ہے تو اپکرن لگانے کا کام کس روپ میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کاریئے ورش ۱۹۹۶ میں کیسے سمپن ہو سکے گا۔

श्री पी.एस. सईद: आदरणीय माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि धनराशि सरकार सेक्शन कर चुकी हैं। अब वही जगह जो हम को बताई गई हैं, आयडेंटीफाय की गयी हैं, वही जगह हम ने भी एक्सेप्ट की हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट की हैं। अब सिर्फ हमें उस का पजेशन देने की बात हैं और हमारी उम्मीद हैं कि 1996 तक, जब तक कि वह लेंड पजेशन दे देंगे, एकाध महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हम को लेंड पजेशन दे देगी, तब हम 1996 को अंतर्गत ही यह स्कीम लागू कर देंगे।

श्री राजनाथ सिंह : मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी टी.वी. ट्रासंमीटर परियोजना को स्थापित करना होता हैं तो शासन की तरफ से उस क्षेत्र का सर्वे भी कराया जाता हैं कि इस टी.वी.ट्रासंमीटर परियोजना की स्थापना के बाद लाभांवित होंगे? साथ ही मैं यह भी जानकारी चाहूंगा कि इस परियोजना को स्थापित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा कब लिया गया था और माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि धनराशि की मंजूरी दे दी गयी हैं, तो वह धनराशि की मंजूरी कब दी गयी और कितनी राशि मंजूरी दी गयी हैं, इस का भी उत्तर मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा?

श्री पी.एम. सईद : आदरणीय सभापति जी, विद्वान सदस्य ने अपने सवाल में दो पहलू उठाए हैं। अगर मैं उनके सवाल को ठीक से समझ सका हूं तो एक तो उन्होने यह पूछा हैं कि सर्वे करते हैं या नहीं और यह स्कीम लागू करने से कितने लोगों को इस का लाभ पहुंचेगा? सभापति, जी एल.पी.टी. के अंतर्गत लगभग 15 से 20 भी हो सकता है, उतने लोग एल.पी.टी. से लाभांवित हो सकते हैं, ऐसा हमारा सर्वे हैं। दूसरा पहलू उन्होने धनराशि का उठाया हैं। अब यह जो जगह हैं, "एज ए स्पेशल केस" हम ने उस दोनाली जगह को पर्चेज करने के लिए ही तय किया हैं और उस जगह को पर्चेज करने के लिए ही तय किया हैं और उस जगह को पर्चेज करने के लिए 10 हजार रूपए की धनराशि का उन्होने इवैलुएशन रखा हैं। वह रिलीज की गयी हैं, मगर उस के साथ-साथ यह ट्रांसमीटर की कॉस्ट और कोटा केबिन की कास्ट उस के अलहदा हैं। कोटा केबिन का 25 हजार का एसेसमेंट किया गया हैं और ट्रांसमीटर का वह सब मिलाकर इस में 1 लाख से भी ज्यादा धन राशि की जरूरत पड़ती हैं।

सभापति : श्री अनंतराय देवशंकर दवे ।

श्री राजनाथ सिंह : मान्यवर, एक सप्लीमेंटरी और।

MR. CHAIRMAN: No more supplementary. Do you want to put another question? *(Interruptions)*

श्री राजनाथ सिंह : जी हां।

श्री राजनाथ सिंह : जी, क्लैरिफिकेशन। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र मे लो पावर ट्रांसमीटर्स स्थापित किए गए हैं, उनमें से क्या अधिकांश पावर ट्रांसमीटर्स इस समय काम नहीं कर रहे हैं और साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि पर्वतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्वतीय संस्कृति को समृद्व करने के लिए शासन के द्वारा जो प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं क्या यह प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर काम कर रहे हैं? यदि काम कर रहे हैं तो शासन द्वारा इन्हे क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं? और, यदि नहीं काम कर रहे हैं तो यह प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर समुचित रूप से काम करने लगें इस संबंध में शासन कुछ विचार कर रहा हैं?

श्री पी. एम. सईद : सभापति जी, यह जो सवाल हैं यह मुख्य सवाल से नहीं उठता हैं। यह सवाल सिर्फ बासोद वी.एल.पी.टी. की स्थापना से संबंधित हैं, मगर मैं इनके क्लैरिफिकेशन का जवाब दे सकता हूं। ...(**व्यवधान**)... दो मिनट में मेरे पास जो इंफोरमेशन हैं, मैं इनसे शेयर करना चाहूंगा। वह यह कि जो वह एच.पी.टी. था या आपने प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर के बारे में पूछा कि वह कहां कहां अभी काम करते हैं, आपको वह मालूम होगा, मैं यहां पर बता सकता हूं कि हाई पावर ट्रांसमीटर ...(**व्यवधान**)...

†Transliteration in Arabic Script

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैंने यह जानना चाहा हैं कि लो पावर ट्रांसमीटर पर्वतीय क्षेत्र में इस समय काम नहीं कर रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद : सर, यह कौन से पर्वतीय क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, अगर माननीय सदस्य कुछ जानकारी देते हैं तो जरूर हम उसके ऊपर पूछताछ करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा हैं। ऐसे ही एक जनरल कहने से नहीं होगा। सर, ऐसे ही एक जनरल कहने से नहीं होगा। सर, ऐसी कंपलेंट कहीं भी नहीं हैं। एक बात हैं कि जहां पर्वतीय क्षेत्र में जैसा एल.पी.पी.टी. हो या वी.एल.पी.टी. हो, वह काम करते हों, उनका जितने क्षेत्र में लाभ होना हैं वह कभी कभी नहीं होता क्योंकि पर्वत उसके बीच में आता हैं। इसलिए जितना एरिया वह कवर नहीं करते हैं उसके लिए दूसरा कोई ट्रासमीटर लगाने की हमें जरूरत पड़ती हैं। कोई भी ऐसी जगह की शिकायत अगर माननीय सदस्य बताएंगे तो जरूर हम उसके बारे में सोचेंगे।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, यह मेरा सवाल सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ हैं। राजस्थान और गुजरात जो बोर्डर एरिया के स्टेट हैं, उसके बारे में सरकार ने पहले ही यह तय किया था कि पाकिस्तान की ओर से हमारे ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा हैं और इसलिए सरकार ने इन दोनों स्टेटों में टी.वी. स्टेशन डालने के लिए कहीं जगह भी ली, कुछ काम भी चल रहा हैं। यह सांस्कृतिक आक्रमण दिन-प्रति-दिन हमारी और बढता जा रहा हैं। यह मामला इस सदन में बहुत बार उठ चुका हैं। तो सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन दो स्टेट के बोर्डर एरिया पर कितने टी.वी. स्टेशन शुरू करने के काम शुरू किए हैं? कब किए हैं और वह कब पूरे होंगे?

श्री पी.एम. सईद : सभापति जी, यह एक दूसरा ही सवाल उठाया गया हैं। यह दो स्टेट में पाकिस्तान से हमारी कल्चरल हैरिटेज पर जो आक्रमण हो रहा हैं, इसके बारे में हैं।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मंत्री जी, सुनिए। यह देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ टी.वी. स्टेशन का ही सवाल हैं। आपके पास सारी माहिती होनी ही चाहिए।

श्री पी.एम. सईद : मेरे पास तो हैं ही, मगर यह सवाल अलग सवाल हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : तो दीजिए। इसमें कोई अलग नोटिस की जरूरत हैं ही नहीं।

SHRI P.M. SAYEED: Sir, I seek your protection. Sir, the question relates to the location of land identified for setting up a low power TV transmitter at Basot...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: You have to put a separate question for that. *(Interruptions)*

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : यह डिफरेण्ट नहीं हैं, सर। ...(**व्यवधान**)... देश की सुरक्षा का सवाल हैं, बिल्कुल देश की सुरक्षा का सवाल हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI P.M. SAYEED: Even then I will be in a position to reply to his question. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, would you still like to say something?

SHRI P.M. SAYEED: Yes, Sir. Even though the question put by the hon. Member is not concerned with the main question, it is correct that our neighbouring countries, particularly Pakistan... *(Interruptions)*

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैंनें पार्टिकुलरली बताया। ...(**व्यवधान**)...

SHRI P.M. SAYEED: Do you not want me to answer it? Please hear me. It is not arising out of this question but still I am trying to answer it. The cultural heritage of India is a model to the rest of the world. What we are doing is not for these two States alone but for the entire country. We are allocating large amounts of money which we collect from Doordarshan programmes. We have spent almost the entire money on building up our hardware, our machines and infrastructure so that we can prepare software for our cultural heritage and in a massive way, in an aggressive way, we will have to do that. That is the only answer to the broadcasting done by any of the neighbouring countries. There is nothing new in it. We are at it. We will go in a massive way.